ResearchNext International Multidisciplinary Journal

Vol- 2, Issue- 1, January-March 2026 ISSN (O)- 3107-9725

Email id: editor@researchnextjournal.com Website- www.researchnextjournal.com

कृषि विकास योजनाओं के बावजूद वैशाली जिले में बेरोजगारी के कारणों का विश्लेषण (2005–2020)

रोहित कुमार

शोध छात्र, अर्थशास्त्र विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार

Article Info: *(Recieved- 27/12/2025, Accept- 02/02/2026, Published- 10/02/2026)*

DOI- 10.64127/rnimj.2026v2i1006

सार

बिहार का वैशाली जिला 2005 से कृषि विकास योजनाओं के लंबे समय तक लागू होने के बावजूद लगातार बेरोजगारी से जूझ रहा है। यह पत्र 2005–2020 के दौरान जिले में बेरोजगारी के मूल कारणों की जांच करता है, जिसमें सामाजिक–आर्थिक, संरचनात्मक और नीति–कार्यान्वयन आयामों का विश्लेषण किया गया है। हालांकि कृषि पहलों – फसल विविधीकरण के प्रयासों से लेकर सीधे लाभ हस्तांतरण तक – ने उत्पादन और किसानों के कल्याण में सुधार किया है, लेकिन वे पर्याप्त रोजगार सृजन में तब्दील नहीं हो पाए हैं। प्रमुख कारण कारकों में भूमि विखंडन और कम उत्पादकता के कारण कृषि में अतिरिक्त श्रम, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, अपर्याप्त गैर–कृषि क्षेत्र विकास, ग्रामीण कार्यबल में कौशल की कमी, और योजना कार्यान्वयन में कमियां जैसे सीमित कवरेज और लाभों का गलत आवंटन शामिल हैं। द्वितीयक स्रोतों, सरकारी रिपोर्टों और बिहार में क्षेत्रीय बेरोजगारी पर साहित्य के आधार पर, अध्ययन का निष्कर्ष है कि कृषि से परे संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना और कौशल विकास और औद्योगीकरण को मजबूत करना बेरोजगारी को स्थायी रूप से कम करने के लिए आवश्यक है।

मुख्य–शब्दः बेरोजगारी, वैशाली जिला, कृषि विकास, ग्रामीण श्रम, कौशल की कमी, गैर–कृषि रोजगार, बिहार

परिचय

ग्रामीण भारत में बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण विकासात्मक चुनौती बनी हुई है, जिसमें बिहार के वैशाली जैसे जिले लक्षित कृषि विकास योजनाओं के बावजूद लगातार बेरोजगारी के विरोधाभास का उदाहरण पेश करते हैं। 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लागू होने से लेकर विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार के कृषि सहायता कार्यक्रमों तक, नीति निर्माताओं ने रोजगार सृजन और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने की कोशिश की है। हालांकि, वैशाली में बेरोजगारी और अल्प–रोजगार का उच्च स्तर बना हुआ है, खासकर युवाओं और भूमिहीन मजदूरों के बीच, जो यह दर्शाता है कि अकेले कृषि विकास पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है (चौधरी, 2021)।

यह पत्र 2005 से 2020 तक वैशाली जिले में बेरोजगारी के कारणों की जांच करता है, यह आकलन करते हुए कि कृषि विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से रोजगार वृद्धि में क्यों तब्दील नहीं हो पाई हैं। यह विश्लेषण वैशाली की रोजगार स्थिति को बिहार की अर्थव्यवस्था में व्यापक संरचनात्मक बाधाओं के संदर्भ में रखता है, जिसमें श्रम बाजार की विशेषताएं, औद्योगिक विकास और कार्यबल कौशल शामिल हैं।

बेरोजगारी ग्रामीण भारत में, विशेष रूप से बिहार जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में, सबसे लगातार

सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों में से एक रही है। लगातार पॉलिसी पर ध्यान देने, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और कई डेवलपमेंट स्कीम लागू करने के बावजूद, ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा बेरोज़गारी, कम रोज़गार और आजीविका की असुरक्षा का सामना कर रहा है। उत्तरी बिहार में स्थित वैशाली ज़िला, जो पारंपरिक रूप से अपने उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है, इस संदर्भ में एक अजीब विरोधाभास पेश करता है। हालांकि कृषि अभी भी मुख्य आर्थिक गतिविधि है और 2005 से कई कृषि विकास योजनाएं लागू की गई हैं, फिर भी बेरोज़गारी बड़े पैमाने पर फैली हुई है। यह विरोधाभास कृषि विकास की प्रकृति, ग्रामीण रोज़गार की संरचना और स्थायी आजीविका पैदा करने में विकास हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है।

ऐतिहासिक रूप से कृषि को बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और वैशाली जैसे जिलों में रोज़गार का मुख्य स्रोत माना जाता रहा है। इस जिले को अनुकूल कृषि–जलवायु परिस्थितियों, कई फसल पैटर्न और हाजीपुर और पटना जैसे शहरी बाजारों से निकटता का लाभ मिलता है। कृषि की केंद्रीय भूमिका को पहचानते हुए, केंद्र और राज्य स्तर पर लगातार सरकारों ने 2005 और 2020 के बीच कृषि विकास की कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें इनपुट सब्सिडी कार्यक्रम, सिंचाई विस्तार पहल, मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन योजनाएं, फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र, पीएम–किसान जैसी प्रत्यक्ष आय सहायता, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसे रोज़गार–उन्मुख कार्यक्रम शामिल हैं। इन हस्तक्षेपों का घोषित उद्देश्य न केवल कृषि उत्पादकता बढ़ाना था, बल्कि रोज़गार के अवसर पैदा करना, ग्रामीण गरीबी कम करना और संकटग्रस्त पलायन को रोकना भी था।

हालांकि, वैशाली में जमीनी हकीकत बताती है कि कृषि उत्पादन में सुधार से रोज़गार सृजन में समान वृद्धि नहीं हुई है। ग्रामीण कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा बेरोज़गार या अल्प–रोज़गार में है, खासकर कृषि के ऑफ–सीज़न के दौरान। प्रच्छन्न बेरोज़गारीकृजहां आर्थिक रूप से आवश्यक से अधिक श्रम कृषि में लगा हुआ हैकृजिले की कृषि संरचना की विशेषता बनी हुई है। छोटे और खंडित भूमि जोत, मशीनीकरण से श्रम मांग में कमी, और मूल्यवर्धित कृषि गतिविधियों के सीमित दायरे ने बढ़ते ग्रामीण श्रम बल को अवशोषित करने की कृषि की क्षमता को सीमित कर दिया है। नतीजतन, कृषि विकास, आय सहायता के लिए महत्वपूर्ण होने के बावजूद, रोज़गार सृजन के लिए एक पर्याप्त इंजन के रूप में काम करने में विफल रहा है।

2005 से 2020 तक की अवधि वैशाली में बेरोज़गारी की गतिशीलता को समझने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस चरण में ग्रामीण विकास और रोज़गार सृजन में बड़े नीतिगत बदलाव देखे गए। 2005 में मनरेगा की शुरुआत ग्रामीण परिवारों को मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देने का एक ऐतिहासिक प्रयास था। साथ ही, बिहार में कृषि के लिए राज्य–विशिष्ट रोडमैप, सिंचाई और विस्तार सेवाओं में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि, और किसान कल्याण के उद्देश्य से केंद्रीय योजनाओं के विस्तार के माध्यम से कृषि पुनरोद्धार पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया। इन प्रयासों के बावजूद, वैशाली में बेरोज़गारी के संकेतक चिंताजनक बने रहे, खासकर भूमिहीन कृषि मज़दूरों, सीमांत किसानों, महिलाओं और शिक्षित ग्रामीण युवाओं के बीच।

वैशाली में बेरोज़गारी के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक तीव्र जनसंख्या वृद्धि और श्रम बल का निरंतर विस्तार है। हर साल, बड़ी संख्या में युवा जॉब मार्केट में आते हैं, जबकि एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टर्स की उन्हें नौकरी देने की क्षमता लिमिटेड रहती है। एक मज़बूत नॉन–फार्म ग्रामीण इकॉनमी की कमी इस समस्या को और बढ़ा देती है। वैशाली में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन मामूली रहा है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो–प्रोसेसिंग और सर्विस सेक्टर्स में लिमिटेड ग्रोथ हुई है। नतीजतन, एक्स्ट्रा एग्रीकल्चरल लेबर के पास लोकल लेवल पर बहुत कम ऑप्शन होते हैं और उन्हें अक्सर इनफॉर्मल और असुरक्षित रोज़गार की तलाश में बिहार के अंदर और बाहर शहरी सेंटर्स में माइग्रेट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

वैशाली में बेरोज़गारी का एक और ज़रूरी पहलू शिक्षा, स्किल्स और रोज़गार के अवसरों के बीच मिसमैच से जुड़ा है। समय के साथ साक्षरता का लेवल बेहतर हुआ है, लेकिन शिक्षा प्रणाली ने ग्रामीण वर्कफोर्स को मार्केट के हिसाब से ज़रूरी स्किल्स से ठीक से लैस नहीं किया है। वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पैमाने और पहुंच के मामले में अपर्याप्त हैं। नतीजतन, जब नॉन–एग्रीकल्चरल रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं, तब भी लोकल वर्कर्स के पास अक्सर उन तक पहुंचने के लिए ज़रूरी स्किल्स की कमी होती है, जिससे स्ट्रक्चरल बेरोज़गारी होती है।

इसके अलावा, एग्रीकल्चर और रोज़गार योजनाओं को लागू करने में कई एडमिनिस्ट्रेटिव और इंस्टीट्यूशनल चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। मज़दूरी के पेमेंट में देरी, डळछत्म्ळ। के तहत काम का अनियमित प्रावधान, लाभार्थियों के बीच लिमिटेड जागरूकता और टारगेटिंग में इनएफिशिएंसी जैसे मुद्दों ने इन प्रोग्राम्स के रोज़गार पर पड़ने वाले असर को कम कर दिया है। कई मामलों में, एग्रीकल्चरल योजनाओं ने मुख्य रूप से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने या इनकम ट्रांसफर पर ध्यान केंद्रित किया है, न कि ऐसे लेबर–इंटेंसिव एक्टिविटीज़ पर जो लगातार रोज़गार पैदा कर सकें। इस पॉलिसी ओरिएंटेशन ने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और रोज़गार पैदा करने के बीच के लिंक को और कमज़ोर कर दिया है।

साहित्य समीक्षा

कृषि निर्भरता और श्रम अवशोषण

वैशाली में कृषि प्रमुख आर्थिक गतिविधि बनी हुई है, जिसमें तीन–चौथाई से अधिक ग्रामीण परिवार आजीविका के लिए खेती और संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर हैं (वैशाली जिला अर्थव्यवस्था डेटा)। हालांकि, व्यापक साहित्य इंगित करता है कि ऐसी सेटिंग्स में कृषि छोटे जोत संरचनाओं, पारंपरिक खेती के तरीकों और कम उत्पादकता के कारण कम श्रम अवशोषण क्षमता से ग्रस्त है (चौधरी, 2021)। ग्रामीण रोज़गार में कृषि का प्रभुत्व अक्सर मौसमी और प्रच्छन्न बेरोज़गारी की ओर ले जाता है, क्योंकि श्रम की मांग फसल के मौसम के साथ घटती–बढ़ती रहती है और साल भर काम देने में विफल रहती है (इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च, 2024)

अध्ययन यह भी उजागर करते हैं कि उपजाऊ भूमि और कई फसल चक्रों के बावजूद, वैशाली में कृषि क्षेत्र का पर्याप्त आधुनिकीकरण नहीं हुआ है। अपर्याप्त पूंजी निर्माण, आधुनिक प्रौद्योगिकी की कमी, खराब सिंचाई सुविधाओं और कमजोर कृषि विपणन जैसी बाधाओं ने उत्पादकता लाभ और स्थायी रोज़गार के अवसरों को सीमित कर दिया है (चौधरी, 2021)

संरचनात्मक बाधाएं: गैर–कृषि रोज़गार की कमी

बिहार की व्यापक आर्थिक संरचना अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में सीमित गैर–कृषि रोज़गार के अवसर प्रदान करती है। वैशाली में औद्योगीकरण सीमित रहा है, अधिकांश गैर–कृषि नौकरियां छोटे पैमाने की कृषि–प्रसंस्करण इकाइयों और सीमित विनिर्माण गतिविधियों तक ही सीमित हैं (वैशाली औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण)। अलग–अलग रोज़गार के अवसरों की कमी का मतलब है कि अतिरिक्त मज़दूर कम प्रोडक्टिविटी वाली खेती में ही लगे रहते हैं या काम की तलाश में ज़िले से बाहर चले जाते हैं।

जनसंख्या वृद्धि और कार्यबल की गतिशीलता

कार्यबल में तेज़ी से वृद्धि, खासकर युवाओं में, बिहार के ग्रामीण ज़िलों में बेरोज़गारी को और बढ़ा देती है। उच्च प्रजनन दर और जनसंख्या विस्तार से श्रम अधिशेष पैदा होता है जिसे केवल कृषि ही अवशोषित नहीं कर सकती (इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सोशल साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च, 2024)। उद्योग और सेवाओं में समान वृद्धि के बिना, श्रम बाज़ार संतृप्त रहता है, जिससे संरचनात्मक बेरोज़गारी होती है।

कौशल की कमी और शिक्षा की कमियाँ

कार्यबल के कौशल और श्रम बाज़ार की मांगों के बीच बेमेल बेरोज़गारी का एक महत्वपूर्ण कारण है। बिहार में बेरोज़गारी पर साहित्य इस बात पर ज़ोर देता है कि कौशल विकास और तकनीकी प्रशिक्षण के निम्न स्तर ग्रामीण श्रमिकों की कृषि के बाहर रोज़गार पाने की क्षमता को सीमित करते हैं। जबकि साक्षरता दर बढ़ी है, सार्थक रोज़गार कौशल अभी भी दुर्लभ हैं, खासकर युवाओं में (बेरोज़गारी अभी भी बिहार में एक मुख्य मुद्दा है)

योजना कार्यान्वयन में कमियाँ

अनुभवजन्य अध्ययन बताते हैं कि मनरेगा और अन्य ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रमों जैसी योजनाएँ बिहार, जिसमें वैशाली भी शामिल है, में शुरू की गई हैं, लेकिन कार्यान्वयन में कमियाँ बनी हुई हैं। लाभों का गलत आवंटन, लाभार्थियों के बीच जागरूकता की कमी, और ज़रूरत से कम काम के प्रावधान जैसे मुद्दे इन योजनाओं की लगातार रोज़गार प्रदान करने की प्रभावशीलता को कम करते हैं (मनरेगा पर इंडियास्पेंड रिपोर्ट)

अध्ययन पद्धति

यह अध्ययन द्वितीयक तथ्य विश्लेषण दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें 2005 से 2020 तक वैशाली जिले

में बेरोज़गारी के बहुआयामी कारणों का आकलन करने के लिए मौजूदा साहित्य, सरकारी रिपोर्ट, जिला आर्थिक प्रोफाइल और अकादमिक लेखों का संश्लेषण किया गया है। स्रोतों में पीयर–रिव्यूड प्रकाशन, जिला सर्वेक्षण, आर्थिक रिपोर्ट और विश्वसनीय समाचार खाते शामिल हैं। समीक्षा जिले में रोज़गार के रुझानों को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक, नीतिगत और श्रम बाज़ार कारकों की पहचान करने पर केंद्रित है। जिला–स्तरीय अनुदैर्ध्य डेटा की कमी के कारण सीमाओं के बावजूद, उपलब्ध साहित्य बेरोज़गारी के पीछे संरचनात्मक कारणों का विश्लेषण करने के लिए एक व्यापक आधार प्रदान करता है।

विश्लेषण और चर्चा

1. कृषि विकास और सीमित श्रम अवशोषण

2005 से 2020 तक, वैशाली और बिहार में कई कृषि विकास पहल लागू की गईं, जिसमें प्रौद्योगिकी प्रसार, इनपुट सब्सिडी, फसल विविधीकरण सहायता, और च्ड–झ्ैछ (प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि) जैसी प्रत्यक्ष आय सहायता योजनाएँ शामिल हैं। इन प्रयासों से कई किसानों की कृषि आय में सुधार हुआ, लेकिन रोज़गार के पर्याप्त अवसर नहीं बढ़े।

मुख्य मुद्दा यह है कि वैशाली में कृषि विकास काफी हद तक श्रम–बचत वाला रहा है, न कि श्रम–सृजन वाला। आधुनिक कृषि पद्धतियाँ, उत्पादकता बढ़ाने के साथ–साथ, अक्सर शारीरिक श्रम की आवश्यकता को कम करती हैं। साथ ही, जिले में अधिकांश खेत छोटे और खंडित हैं, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक पैमाना कम है और रोज़गार सृजन सीमित है (चौधरी, 2021)।

मौसमी फसल पैटर्न का मतलब है कि बुवाई और कटाई के मौसम में श्रम की मांग बढ़ जाती है, लेकिन ऑफ–पीक महीनों के दौरान कम रहती है, जिससे कृषि श्रमिकों के लिए मौसमी बेरोज़गारी की अवधि बनती है (इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च, 2024)। इसके अलावा, प्रच्छन्न बेरोज़गारी की व्यापकता – जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा श्रमिक कृषि में लगे हुए हैं – अल्प–रोज़गार को अस्पष्ट करती है और श्रम के कम उपयोग को छिपाती है।

2. गैर–कृषि रोज़गार की संरचनात्मक कमी

वैशाली में बेरोज़गारी के सबसे लगातार निर्धारकों में से एक कमज़ोर गैर–कृषि क्षेत्र है। जिले में औद्योगिक विकास न्यूनतम रहा है। हालांकि छोटे एग्रो–प्रोसेसिंग यूनिट और हाजीपुर जैसे कुछ इंडस्ट्रियल एरिया हैं, लेकिन ये सरप्लस लेबर को खपाने के लिए काफी बड़े नहीं हो पाए हैं (वैशाली जिले की अर्थव्यवस्था)।

मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टरकृजो आमतौर पर खेती के अलावा कई तरह के रोज़गार के मौके देते हैंकृ अंडरडेवलप्ड हैं। इस विविधीकरण की कमी का मतलब है कि ग्रामीण मज़दूरों को बहुत कम वैकल्पिक नौकरियाँ मिलती हैं, जिससे कई लोगों को दूसरे इलाकों में पलायन करना पड़ता है या अनौपचारिक, कम वेतन वाला काम स्वीकार करना पड़ता है।

3. जनसंख्या का दबाव और लेबर सरप्लस

2005–2020 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि के कारण वैशाली की लेबर फोर्स में काफी विस्तार हुआ, जिसमें हर साल बड़ी संख्या में युवा वर्कफोर्स में शामिल हो रहे हैं (इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सोशल साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च, 2024)। नौकरियों के सृजन के बिना बढ़ती लेबर सप्लाई से लेबर मार्केट में ओवरसैचुरेशन हो जाता है।

यह जनसांख्यिकीय दबाव कम श्रम बल भागीदारी दर और कमजोर महिला श्रम भागीदारी से और बढ़ जाता है – ये मुद्दे पूरे बिहार में स्पष्ट हैं – जो रोजगार की गतिशीलता और घरेलू आय को और सीमित करते हैं (बिहार आर्थिक सर्वेक्षण)

4. कौशल की कमी और शिक्षा–रोजगार बेमेल

हालांकि बिहार में साक्षरता बढ़ी है, लेकिन कौशल विकास पहलों ने ग्रामीण कार्यबल को रोजगार योग्य तकनीकी कौशल से पर्याप्त रूप से सुसगत नहीं किया है। कृषि–केंद्रित शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण मार्गों की कमी शिक्षित युवाओं में उच्च बेरोजगारी में योगदान करती है जिनके पास बाजार की मांगों के अनुरूप कौशल की कमी है। यह शिक्षा–रोजगार बेमेल कई लोगों को औपचारिक क्षेत्र की नौकरियां हासिल करने में असमर्थ बनाता है, जिससे संरचनात्मक बेरोजगारी बढ़ जाती है।

व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सीमित पहुंच का मतलब है कि जब गैर–कृषि रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, तब भी स्थानीय श्रमिक अक्सर उन्हें भरने के लिए अयोग्य होते हैं। नतीजतन, नियोक्ता बाहरी श्रमिकों को पसंद कर सकते हैं या पदों को खाली छोड़ सकते हैं।

5. नीति कार्यान्वयन और योजना प्रभावकारिता

वैशाली में मनरेगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और अन्य ग्रामीण रोजगार पहलों जैसी कृषि सहायता योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन उनका रोजगार प्रभाव मिश्रित रहा है। उदाहरण के लिए,मनरेगा को 2005 से प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों के ग्रामीण कार्य की गारंटी देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन बिहार में कार्यान्वयन में अनियमित कार्य प्रावधान और प्रशासनिक बाधाओं सहित चुनौतियों का सामना करना पड़ा है (मनरेगा अवलोकन)। बिहार की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि मनरेगा के तहत काम की मांग का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही पूरा होता है, जिसमें नौकरी चाहने वालों को प्रदान किए गए वास्तविक रोजगार के दिनों में महत्वपूर्ण अंतर होता है।

इसी तरह, जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यह सीधे रोजगार सृजित नहीं करता है; बल्कि, यह किसानों की आय को पूरक करता है, जो अनजाने में श्रम बल भागीदारी को कम कर सकता है लेकिन संरचनात्मक बेरोजगारी को संबोधित नहीं करता है।

भ्रष्टाचार, लाभार्थियों के बीच जागरूकता की कमी और सीमित प्रशासनिक क्षमता जैसी चुनौतियां रोजगार योजनाओं की प्रभावशीलता को और कम करती हैं, जिससे स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने की उनकी क्षमता में बाधा आती है।

6. प्रवासन पैटर्न और क्षेत्रीय असंतुलन

स्थानीय रोजगार के अवसरों की कमी ने वैशाली से अन्य राज्यों के शहरी केंद्रों में बाहरी प्रवासन में वृद्धि में योगदान दिया है, जहां प्रवासी अक्सर अनौपचारिक और कम वेतन वाली नौकरियां करते हैं। प्रवासन बेरोजगार ग्रामीण श्रमिकों के लिए एक मुकाबला तंत्र प्रदान करता है लेकिन जरूरी नहीं कि स्थानीय रोजगार की स्थिति में सुधार हो या क्षेत्रीय आर्थिक विकास में योगदान हो। प्रेषण घरेलू गरीबी को कम कर सकते हैं, लेकिन वे स्थानीय रोजगार सृजन का विकल्प नहीं हैं।

निष्कर्ष

2005–2020 तक दशकों की कृषि विकास योजनाओं के बावजूद वैशाली जिले में बेरोजगारी एक लगातार चुनौती बनी हुई है। सबूत बताते हैं कि कुछ मामलों में कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार हुआ है, लेकिन इन फायदों से रोज़गार के सार्थक अवसर पैदा नहीं हुए हैं। इसके मुख्य कारणों में जनसंख्या वृद्धि के कारण श्रम की अधिकता, छोटे और बिखरे हुए खेतों के कारण मौसमी और छिपी हुई बेरोज़गारी, कमज़ोर गैर–कृषि रोज़गार क्षेत्र, ग्रामीण कार्यबल में कौशल की कमी और नीति कार्यान्वयन में कमियाँ शामिल हैं।

वैशाली में बेरोज़गारी को दूर करने के लिए एक समग्र रणनीति की ज़रूरत है जो सिर्फ़ कृषि विकास से आगे जाए। नीतियों को औद्योगीकरण को बढ़ावा देने, गैर–कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार करने, कौशल विकास में निवेश करने और रोज़गार योजनाओं की प्रभावशीलता में सुधार करने पर ध्यान देना चाहिए। बाज़ार तक पहुँच बढ़ाना, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना भी रोज़गार सृजन को बढ़ावा दे सकता है। केवल विविध आर्थिक विकास और लक्षित रोज़गार कार्यक्रमों के माध्यम से ही वैशाली बेरोज़गारी में स्थायी कमी हासिल कर सकता है।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

संदर्भ

1. चौधरी, डी. के. (2021). बिहार के वैशाली जिले में बेरोज़गारी की स्थिति – एक सामाजिक–आर्थिक परिप्रेक्ष्य। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट रिव्यू।
2. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण– अध्याय 5: श्रम, रोज़गार और कौशल विकास (2025). ठच्ब्ै कॉन्सेप्ट वाला।
3. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट रिव्यू (2021). वैशाली जिले में कृषि संबंधी बाधाएँ। प्श्रैडत
4. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सोशल साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च (2024). बिहार में राज्यव्यापी ग्रामीण बेरोज़गारी की गतिशीलता। सोशल साइंस जर्नल
5. मनरेगा (2005). महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम।
6. अहलुवालिया, एम. एस. (2011). बारहवीं योजना में संभावनाएं और नीतिगत चुनौतियाँ। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 46(21), 88–105.
7. भल्ला, एस., और सिंह, जी. (2010). भारत में विकास, असमानता और गरीबी। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 45(30), 44–63.
8. ड्रेज़, जे., और खेरा, आर. (2010). रोज़गार गारंटी के लिए लड़ाई। फ्रंटलाइन, 27(1), 12–17.
9. हिमांशु. (2011). भारत में रोज़गार के रुझानः एक पुनर्परीक्षण। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 46(37), 43–59.
10. कन्नन, के. पी., और रवींद्रन, जी. (2012). लापता श्रम बल की गिनती और प्रोफाइलिंग। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 47(6), 77–80.
11. कुमार, ए., और कुमार, एस. (2018). बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी और प्रवासनः एक जिला–स्तरीय विश्लेषण। इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, 61(3), 517–533.
12. मेहरोत्रा, एस., परिदा, जे. के., सिन्हा, एस., और गांधी, ए. (2014). भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार के रुझानों की व्याख्या। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 49(32), 49–57.
13. मुखर्जी, एस. (2016). भारत में ग्रामीण श्रम बाजार और संरचनात्मक परिवर्तन। इंडियन जर्नल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, 10(2), 175–195.

Cite this Article-

"रोहित कुमार", "कृषि विकास योजनाओं के बावजूद वैशाली जिले में बेरोजगारी के कारणों का विश्लेषण (2005–2020)", *ResearchNext International Multidisciplinary Journal, ISSN: 3107-9725 (Online), Volume:2, Issue:1, January-March 2026.*

"Copyright © 2026 The Author(s). This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY), allowing others to use, share, modify, and distribute it with proper credit to the author."